



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 39]

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 26, 1970 (आश्विन 4, 1892)

No. 39]

NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 26, 1970 (ASVINA 4, 1892)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

नोटिस

(NOTICE)

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 22 जुलाई 1970 तक प्रकाशित किये गये हैं :—

The undermentioned Gazettes of India Extraordinary were published up to 22nd July 1970 :—

अंक (Issue No.)	संख्या और तिथि (No. and Date)	द्वारा जारी किया गया (Issued by)	विषय (Subject)
1	2	3	4

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी।
मांग-पत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिए।

Copies of the Gazette Extraordinary mentioned above will be supplied on indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची (CONTENTS)

भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	743	भाग II—खंड 3—उप-खंड (2)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	4053
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1167	भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	585
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	—	भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संलग्न तथा अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	1065
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1181	भाग III—खंड 2—एकत्र कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसें	369
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—	भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	145
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों सम्बन्धी प्रश्न समितियों की रिपोर्टें	—	भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं	1065
भाग II—खंड 3—उप-खंड (1)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	3289	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें	169
		पूरक संख्या 39—	
		19 सितम्बर 1970 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी सम्बन्धी साप्ताहिक रिपोर्ट	1603
		30 अगस्त 1970 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु से सम्बन्धित आंकड़े	1615
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	743	PART II—SECTION 3.—Sub-Sec. (ii) —Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	4053
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1167	PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence	585
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	—	PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1065
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	1181	PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta..	369
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—	PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	145
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—	PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1065
PART II—SECTION 3.—Sub-Sec. (i)—General Statutory Rules (including orders, by-laws etc., of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	3289	PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	169
		SUPPLEMENT No. 39	
		Weekly Epidemiological Reports for week ending 19th September 1970	1603
		Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week ending 30th August 1970	1615

भाग I—खण्ड 1 PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं
[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 सितम्बर, 1970

सं० 46-प्रजे०/70—राष्ट्रपति केन्द्रीय आरक्षित पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं।

अधिकारियों के नाम और पद

श्री ब्रह्म दास,

नायक सं० 22351,

19वीं बटालियन, केन्द्रीय आरक्षित पुलिस।

श्री जान,

कांस्टेबल सं० 21938,

19वीं बटालियन, केन्द्रीय आरक्षित पुलिस।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

30 जून, 1969 को आन्ध्र प्रदेश की कंकागिरि पहाड़ियों में कतिपय उग्रवादियों की गतिविधियों को रोकने तथा उनके छिपने के स्थानों का पता लगाने के लिए केन्द्रीय आरक्षित पुलिस की 19वीं बटालियन का एक गश्ती दल गश्त पर गया। 1 जुलाई, 1969 को उस दल ने पहाड़ी की चोटी की ओर जाते वाने जंगली मार्ग पर चावल के दाने तथा सिगरेट के टोटे देखे। उस दल को शक हुआ कि उग्रवादी उसी क्षेत्र में हैं और उनका सुराख लगाने चल पड़े।

दल ने पहाड़ी पर बढ़ना आरम्भ किया। जब वे पहाड़ी की चोटी से कोई 100 गज दूर रहे तो उन पर गोली चलाई गई। उनका आगे बढ़ना रुक गया क्योंकि वह दल प्रतिकूल स्थिति में था और उन पर आक्रमण करना आसान था क्योंकि वे चोटी से नीचे थे और वहां गोली से कोई बचाव न था। गिरोंह का पता लगाने की प्रक्रिया में इस गश्ती दल के एक सदस्य कांस्टेबल जान (सं० 21938) ने गिरोंह के एक सदस्य को देख लिया जो एक बड़ी चट्टान की आड़ से गोली चला रहा था। अपने प्राणों की कोई परवाह न करते हुए उन्होंने पहल की और बड़े साहस से लगभग 50 गज रेंग कर आगे बढ़े और सावधानीपूर्वक निशाना बांधकर उस पर गोली चलाई। उसके तुरन्त बाद नायक ब्रह्म दास ने अपने सिपाहियों को विरोधी चौकी पर आक्रमण करने का आदेश दिया। आक्रमणकारी दल के पहाड़ी की चोटी तक पहुंचने की प्रतीक्षा में रुक कर सं० 21938 कांस्टेबल जान भी चलाई गई गोली से घायल व्यक्ति को भी वहीं छोड़ भाग निकले।

केन्द्रीय आरक्षित पुलिस की टुकड़ी ने 12 बोर गोला-बारूद के बिना बले 2 कारतूस, एक मुइयां डाकू, 4 बाले, 8 देसी बम, कुछ खाकी वर्दियां, दस्तावेजों का एक पुलन्दा तथा एक फिलिप्स

ट्रांजिस्टर रेडियो बरामद किया। दस्तावेजों से स्थानीय पुलिस को उस संगठन तथा उसकी गतिविधियों के बारे में उपयोगी जानकारी मिली और उस रेडियो से भी (जिसकी शिनाख्त हो सकती थी) उस गिरोंह के बारे में उपयोगी सूचना प्राप्त हुई।

इस मुठभेड़ में नायक ब्रह्म दास तथा कांस्टेबल जान ने सहाय्य-नीय वीरता, साहस और पहल का परिचय दिया।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं। तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 1 जुलाई, 1969 से दिया जायेगा।

सं० 47-प्रजे०/70—राष्ट्रपति मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिये पुलिस पदक प्रदान करते हैं:—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री कल्याण सिंह,

डैड कांस्टेबल सं० 239,

जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश।

श्री जगदीश सिंह,

कांस्टेबल सं० 296,

जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

कलुवा डाकू का गिरोंह जिला शिवपुरी में उक्तनियाम तथा अपहरण कर रहा था। 25 सितम्बर, 1969 को पुलिस की सूचना मिली कि वह गिरोंह गांव गन्नी बड़ीव के निकट घने जंगल में है। गिरोंह को पकड़ने के लिए पुलिस दल भेजे गये। सर्वश्री कल्याण सिंह तथा जगदीश सिंह उनमें से एक पुलिस दल के स्काउट थे। घने जंगल तथा रात्री के अंधेरे में इन पुलिस कर्मचारियों का शेष दल से सम्पर्क टूट गया और ये अचानक डाकूओं के सामने आ गए। इसमें डाकू पूर्णतया आश्चर्यचकित हो गये और वे इधर-उधर भागने लगे। श्री जगदीश सिंह ने एक डाकू को पकड़ लिया जो मजल-लोडिंग बन्दूक से लैस था। अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की चिन्ता न करते हुए वह सशस्त्र डाकू से भिड़ गया। डाकू ने श्री जगदीश सिंह को गला घोट कर मारने तथा उसका शस्त्र छीनने की चेष्टा की। श्री कल्याण सिंह ने बड़ी सूझ-बूझ से काम लिया, भावधानीपूर्वक निशाना लगाया और डाकू को मार डाला। अंधेरे में एक अन्य डाकू पुलिस दल पर गोली चला रहा था। श्री कल्याण सिंह ने उस पर भी गोली चलाई तथा उसे गम्भीर रूप से घायल कर दिया।

इस मुठभेड़ में श्री कल्याण सिंह तथा श्री जगदीश सिंह ने बड़ा साहस, सूझ-बूझ और कर्तव्य-परायणता दिखाई।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 25 सितम्बर, 1969 से दिया जायेगा।

नागेन्द्र सिंह, राष्ट्रपति के सचिव

**औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)**

नई दिल्ली, दिनांक 8 सितम्बर 1970

सं० 1-11/69-एम० ई० आई०—भूतपूर्व इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय के संकल्प सं० 1-2/63 एम० ई० आई० दिनांक 25 मार्च, 1960 को, जिसके अंतर्गत बाल बियरिंग उद्योग के लिए नामिका का गठन किया है, तथा बाद की अधिसूचना सं० 1-2/63-एम० ई० आई०, दिनांक 14 मई, 1965 को देखें।

2. यह निश्चय किया गया है कि मेसर्स टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी लि० बम्बई का प्रतिनिधित्व श्री जे० ई० तालूलिकर के स्थान पर श्री पी० एस० घायरा, प्रबन्धक (सहायक वस्तु विकास) करेंगे।

टी० वी० एल० नरसय्या, अव्वर सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन, तथा निर्माण, आवास और नगर विकास मंत्रालय

(परिवार नियोजन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 जुलाई 1970

संकल्प

सं० 8-10/69-एम० एम० ओ०/एम० ई०—भारत सरकार 'निरोध सप्ताहकार समिति' का गठन करती है। समिति की रचना इस प्रकार है :—

1. स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर विकास मंत्रालय के राज्यमंत्री, (इंचार्ज परिवार नियोजन) अध्यक्ष
2. स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण, और नगर विकास मंत्रालय के सचिव अथवा उनका मनोनीत व्यक्ति सदस्य
3. डा० डी० पी० करमरकर, आर्थिक अनुसंधान संस्थान, बिद्यागिरी, धारवार सदस्य
4. श्री रसिक लाल पारेख, शंकरभाई बंगलो, महाराष्ट्र सोसाइटी, अहमदाबाद-6 सदस्य
5. आयुक्त, परिवार नियोजन, परिवार नियोजन विभाग। सदस्य

6. डा० आर० सुब्रामणियम, प्रमुख (स्वास्थ्य), योजना आयोग। सदस्य

7. श्री टी० एस० नागराजन, निदेशक, ब्रुक बांड इण्डिया लि० 9-शैक्सपीयर सरणी, कलकत्ता। सदस्य

8. श्री ए० एन० हक्सर, अध्यक्ष, इण्डिया तम्बाकू कं० लि० विर्जीनिया हाऊस, 37, चौरंगी, कलकत्ता। सदस्य

9. मेसर्स हिन्दुस्तान लीवर लि०, बम्बई का प्रतिनिधि। सदस्य

10. मेसर्स लिफ्टन (भारत) लि०, कलकत्ता का प्रतिनिधि। सदस्य

11. मेसर्स टाटा आयल मिल्स कम्पनी लि०, बम्बई का प्रतिनिधि। सदस्य

12. मेसर्स युनियन कारबाईड (भारत) लि०, कलकत्ता का प्रतिनिधि। सदस्य

13. एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन आफ इण्डिया लि० बम्बई का प्रतिनिधि। सदस्य

14. श्री किशन मेहता, महाप्रबंधक, वी कोका कोला एक्सपोर्ट कार्पोरेशन, 14-ए०, पश्चिमी निजामुद्दीन, नई दिल्ली। सदस्य

15. अध्यक्ष, हिन्दुस्तान लेटेक्स लि०, निर्माण भवन, नई दिल्ली। सदस्य संयोजक

16. विजय प्रबन्धक, परिवार नियोजन विभाग। सदस्य संयुक्त संयोजक

2. निरोध के प्रचार, उत्पादन और विक्रय वृद्धि के लिए एक कारगर और समन्वित कार्यक्रम की व्यवस्था करने के उपायों और साधनों पर विचार करना और इस बारे में मार्गदर्शन सम्बन्धी सुझाव देना समिति के विचाराधीन विषय हैं।

3. समिति को अपनी बैठकों में अन्य विशेषज्ञों को चुनने का निमन्त्रण करने का अधिकार होगा।

4. समिति को बैठकों में भाग लेने के लिए समिति के गैर-सरकारी सदस्य यात्रा और दैनिक भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे। ये भत्ते उन्हें उसी दर के अनुसार दिए जाएंगे जो केन्द्रीय सरकार सेवाओं के क्लास 1 के उच्चतम ग्रेड के अधिकारी को स्वीकृत किए जाते हैं। समिति के ऐसे सदस्य जो सरकारी कर्मचारी हैं वे अपने यात्रा और दैनिक भत्ते स्वीकृत दरों के अनुसार उस कार्यालय से प्राप्त करेंगे जहां से उन्हें वेतन मिलता है।

5. यह खर्च वर्ष 1970-71 के चिकित्सा और लोक-स्वास्थ्य के मुख्य शीर्ष 30-लोक स्वास्थ्य ख-लोक स्वास्थ्य ख-5. विविध ख-5(4) परिवार नियोजन पर व्यय ख-5(4)(1) सेवाएं और सामग्री ख-5(4)(1)(4) अनुदान, संख्या 38 के अन्तर्गत निरोध योजना के व्यय के खाते में डाला जाएगा।

आर० एन० मधोक, संयुक्त सचिव

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय (कृषि विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली-1, दिनांक 1970

केन्द्रीय भूमि सुधार समिति

सं० एफ० 11-16/70 मू०सू०ए०—देश में सामाजिक न्याय और कृषि विकास के दृष्टिकोण से भूमि विकास कार्यक्रम ने राष्ट्रीय महत्व ग्रहण कर लिया है। राज्यों द्वारा अपनायी गयी भूमि निति की रूप रेखा प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्रस्तुत की गई थी, द्वितीय योजना में इसका विस्तार किया गया और तृतीय तथा चतुर्थ योजना में इस पर विशेष बल दिया गया।

2. भूमि सुधार कार्यक्रम की प्रगति के निरीक्षण से पता लगता है कि यद्यपि भूमि सुधार उपायों के कार्यान्वयन में पर्याप्त प्रगति हुई है, फिर भी उद्देश्यों तथा कानून बनाने के बीच और कानूनों एवं उनको लागू करने में पर्याप्त अन्तर है।

3. नवम्बर 1969 में खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्री द्वारा आयोजित मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में भूमि सुधार सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से विचार किया गया था। सम्मेलन में भूमि सुधार के उपायों को तेजी से लागू करने के लिए एक न्यूनतम कार्यक्रम बनाने की सिफारिश की गयी। कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, इसलिए सम्मेलन में सभी का यह विचार था कि प्रगति की देख-रेख और राज्यों सरकारों के मार्गदर्शन के लिए एक केन्द्रीय निकाय की स्थापना की जाए। योजना आयोग ने भी केन्द्रीय निकाय की स्थापना का समर्थन किया। इन सिफारिशों का अनुसरण करते हुए एक केन्द्रीय भूमि सुधार समिति की स्थापना की गई है, जिसका गठन निम्न प्रकार होगा :

- | | |
|--|----------|
| (1) खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मन्त्री | —अध्यक्ष |
| (2) विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री | —सदस्य |
| (3) उपाध्यक्ष, योजना आयोग | —सदस्य |
| (4) खाद्य, और कृषि मन्त्रालय में राज्यमन्त्री | —सदस्य |
| (5) गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (गृहकार्य) | —सदस्य |
| (6) सदस्य (कृषि) योजना आयोग | —सदस्य |

प्रधान मन्त्री को भी इस समिति की गतिविधि से अवगत रखा जायेगा।

4. केन्द्रीय समिति राज्य सरकारों के परामर्श से प्रत्येक राज्य से एक या एक से अधिक सदस्य सहयोजित करेगी, जो अपने राज्य से सम्बन्धित कार्यक्रम के बारे में समिति के सदस्य के रूप में कार्य करेंगे।

5. सचिव (कृषि) इस समिति के संयोजक होंगे और भूमि-सुधार कार्यक्रम से सम्बन्धित संयुक्त सचिव इसके संयुक्त संयोजक होंगे।

6. केन्द्रीय समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे :—

- (1) भूमि के स्वामित्व, प्रबन्ध, काश्त पद्धति तथा वितरण सम्बन्धी समस्याओं का निरन्तर अध्ययन करना ;
- (2) भूमि सुधार के कार्यक्रम, निर्धारण तथा कार्यान्वयन में राज्य सरकारों की सहायता करना ;
- (3) व्यक्तिगत स्वामित्व एवं काश्त सीमा लागू करने, लगाने में कमी, पट्टेदारी की सुरक्षा, चकबन्धी करने तथा जोतों के विभाजन को रोकने आदि जैसे भूमि सुधार उपायों की कार्यप्रणाली, उन्नति तथा उनके प्रभाव का समय समय पर मूल्यांकन करना तथा रिपोर्ट देना ;
- (4) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों सहित भूमिहीन कृषि मजदूरों के पुनर्वास के लिए और उन्हें वास भूमि या गृह स्थानों का स्वामित्व प्रदान करने की योजनाओं पर और अन्य सम्बन्धित समस्याओं पर सलाह देना ;
- (5) भूमि सम्बन्धी नीति में उन उपायों और समायोजनों की सिफारिश करना, जो संविधान में निर्धारित राज्य की नीति के निदेशक तत्वों और पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यक्रमों और उद्देश्यों की दृष्टि से जरूरी हों ;
- (6) प्रस्ताव तैयार करने, उपयुक्त कानून बनाने और उन्हें तेजी से लागू करने के लिए राज्यों को सलाह और सहायता प्रदान करना ;
- (7) विशेष समस्याओं, विभिन्न विशेषज्ञों को तथा दीर्घकालीन समस्याएँ ;
स्थापनाधीन भूमि सुधार केन्द्र को अध्ययनार्थ सौंपना ;

7. केन्द्रीय समिति का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में होगा।

8. आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी लिए यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

त्रिभुवन प्रसाद सिंह, सचिव

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 अगस्त 1970

सं० बि० एक-32(84)/68—विद्युत केन्द्रों की लागत और पारेषण हानियों को कम करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन से संबंधित इस मंत्रालय के समसंख्यक संकल्प, दिनांक 27 मई, 1969 के पैरा 3 में निम्नलिखित संशोधन किए जाएं :—

के लिए

पढ़िए

- | | |
|--|--------------------------|
| (5) श्री इपे मथाई, सदस्य (5) श्री पी० पी० गंगाधरन् | |
| (वाणिज्यिक) केन्द्रीय | सदस्य (वाणिज्यिक) |
| जल तथा विद्युत आयोग, | केन्द्रीय जल तथा विद्युत |
| नई दिल्ली। | आयोग। सदस्य |

- (11) श्री बी० बी० देशमुख, (11) श्री बी० बी० देशमुख,
सदस्य, (तकनीकी) अध्यक्ष, भाखड़ा प्रबंधक
महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड, चन्डीगढ़।
बोर्ड, बम्बई। सचिव

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतियां व्यापक प्रचार के लिए विद्युत मितव्ययिता समिति के अध्यक्ष और सदस्यों, सभी राज्य सरकारों और राज्य बिजली बोर्डों को भेज दी जाएं।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

संकल्प

दिनांक 9 सितम्बर 1970

सं० वि० का०-दो-30(208)/70—अलकनंदा नदी ने, जोकि बहुत थोड़े समय में ही अपने सामान्य स्तर से असाधारण रूप से ऊंची चढ़ गई थी, 20 जुलाई, 1970 को अपने तटों को तोड़ दिया, जिसके परिणामस्वरूप तीव्र बाढ़ आई और अगले दिन हरद्वार में गंगा नदी में, जहां पर अपर गंग नहर के हैडवर्क्स स्थित हैं, भारी गाद एकत्र हो गई। उस दिन और उसके पश्चात कुछ दिनों तक नहर की प्रचालन-विधि के परिणामस्वरूप नहर की उपरली पहुंच की 12 किलोमीटर लम्बाई में अत्यधिक गाद एकत्र हो गई और आखिरकार उसे बंद ही कर देना पड़ा। उत्तर प्रदेश सरकार को, नहर के कमानगत क्षेत्र में रबी की सिंचाई सुनिश्चित करने के लिए, एक आपातकालीन विराट गाद-निकासी अभियान तुरंत ही भारी खर्च पर संगठित करना पड़ा। उत्तर प्रदेश सरकार के साथ परामर्श करके, भारत सरकार ने निर्णय किया है कि निम्नलिखित बातों के सम्बन्ध में छान-बीन करने, जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए एक समिति की स्थापना की जाए :—

1. वे कारण जिनके परिणामस्वरूप नहर में गाद जमा हुई;
2. नहर के प्रचालन के लिए वर्तमान नियम एवं विनियम और उनकी यथेष्टता, और यह भी कि उनका पालन बुद्धिमत्तापूर्वक किया गया या नहीं ;
3. ऐसे कोई उपाय जो इस स्थिति का सक्षमतापूर्वक नियंत्रण करने के लिए पहले से ही सोच लेने और कर लेने चाहिए थे,

और साथ ही यह समिति भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक, दोनों से बचने के लिए उपयुक्त सिफारिशें प्रस्तुत करे।

समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे :—

1. श्री एन० जी० के० मूर्ति, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, जल तथा विद्युत विकास सलाहकारी सेवाएं (भारत) लि०, नई दिल्ली। अध्यक्ष
2. श्री एस० के० जैन, अध्यक्ष, केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग, नई दिल्ली। सदस्य
3. श्री जे० पी० नएगामवाला, सदस्य, केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग, नई दिल्ली। सदस्य
4. प्रोफेसर आर० एस० चतुर्वेदी, हरकोर्ट बटलर टेक्नीकल इंस्टिट्यूट, कानपुर। सदस्य
5. श्री जतीन्द्र सिंह, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता (सिंचाई), पंजाब, और सलाहकार, सिंचाई और विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। सदस्य
6. डा० एस० पी० गर्ग, सदस्य-सचिव निदेशक, उत्तर प्रदेश सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रुड़की। सदस्य-सचिव

समिति अपना कार्य तुरंत प्रारम्भ कर देगी और दो महीने के भीतर सिंचाई और विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र भाग I, खण्ड 1 में प्रकाशित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को और सभी राज्य सरकारों/संघीय क्षेत्रों के प्रशासनों को प्रेषित की जाए।

बी० घी० चारि, सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 17th September 1970

No. 46-Pres./70.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Central Reserve Police :—

Names of the officers and ranks.

Shri Brahm Dass,
Naik No. 22351,
19th Battalion, Central Reserve Police.

Shri John,
Constable No. 21938,
19th Battalion, Central Reserve Police.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 30th June, 1969 a patrol party of 19th Battalion Central Reserve Police proceeded on patrolling duty to check the activities of certain extremists in Kankagiri hills, Andhra Pradesh and to find out their hide-outs. On the 1st July, 1969 the party noticed grains of rice and cigarette butts on a jungle track leading towards a hill-top. The party suspected the presence of such extremists in that area and followed the clue.

The party started climbing up the hill. When they were 100 yards short of the hill-top, they were fired upon. The advance was, however, held up due to the party being in a disadvantageous and vulnerable position as

they were on lower ground and were exposed to fire from the top of the hill. In the process of locating the gang, No. 21938 Constable John, a member of the patrol party spotted one among them firing from behind cover of a big rock. In complete disregard of his personal safety, he took the initiative and acting with courage, crawled about 50 yards and took careful aim and shot him. Immediately thereafter, Naik Brahm Dass ordered his men to charge on the hostile post. The extremists did not wait for the attacking party to reach them at the hill-top and fled away leaving behind the injured man shot by No. 21938 Constable John.

The Central Reserve Police party recovered 2 live cartridges of 12 bore ammunition, one folding knife, 4 spears, 8 country made bombs, some khaki uniforms, a bundle of documents and a Philips Transistor Radio. The documents gave useful information regarding the organisation and activities to the local police and together with the Radio (which was indistinguishable) provided useful information about this gang.

In this encounter Naik Brahm Dass and Constable John showed commendable bravery, courage and initiative.

2. These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 1st July, 1969.

No. 47-Pres./70.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Madhya Pradesh Police :—

Names of the officers and ranks.

Shri Kalyan Singh,
Head Constable No. 239,
District Shivpuri,
Madhya Pradesh.

Shri Jagdish Singh,
Constable No. 296,
District Shivpuri,
Madhya Pradesh.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

The gang of dacoit Kalua had been committing dacoities and kidnappings in the Shivpuri District. On the 25th September, 1969, information was received by the Police that the gang was present in the thick jungle near village Garhi Barod. Police parties were sent to round up the gang. Sarvashri Kalyan Singh and Jagdish Singh were the scouts of one of the Police parties. In the thick jungle and darkness of the night, these policemen lost contact with the rest of the party and suddenly came in contact with the dacoits. This completely surprised the dacoits and they ran away helter skelter. Shri Jagdish Singh, however, caught hold of one of the dacoits who was armed with a mizzle loading gun and grappled with him in disregard of his personal safety. The dacoit tried to strangle to death Shri Jagdish Singh and snatch away his weapon. Shri Kalyan Singh showed great presence of mind, took a careful aim and shot dead the dacoit. In the darkness another dacoit was firing at the Police Constables. Shri Kalyan Singh fired at him and injured him seriously.

In this encounter Shri Kalyan Singh and Shri Jagdish Singh showed great courage, presence of mind and devotion to duty.

2. These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 25th September, 1969.

No. 48-Pres./70.—The President is pleased to direct that in Notification No. 19-Pres./57, dated the 26th February, 1957, relating to the Institution of the MERITORIOUS SERVICE MEDAL, the following amendment shall be made :—

In Clause Fourthly, line 3.

for "18 years' service"

substitute "15 years' service"

No. 49-Pres./70.—The President is pleased to direct that in Notification No. 20-Pres./57, dated the 26th February, 1957, relating to the Institution of the LONG SERVICE AND GOOD CONDUCT MEDAL, the following amendment shall be made :—

In Clause Fourthly, lines 3, 4 & 5.

for the words "18 years' combatant or non-combatant service in the Army or in the Air Force or a minimum of 15 years' service in the Navy,"

substitute the words "15 years' combatant or non-combatant service,"

NAGENDRA SINGH, Secy. to the President

CABINET SECRETARIAT

Department of Personnel

New Delhi, the 11th September 1970

CORRIGENDUM

No. 5/35/70-CS(I).—In this Departments Notification No. 5/35/70-CS(I), dated 22nd August, 1970, for Rule 4(1), the following Rule shall be substituted, namely :—

'4. Any permanent or regularly appointed temporary officer of the Assistants' Grade of the Central Secretariat Service who on the 1st July 1970 satisfies the following conditions, shall be eligible to appear at the examination :—

(1) Length of service :—He should have rendered a continuous service of not less than five years in any one or, as the case may be more than one, of the following posts, namely :—

(i) Assistant (C.S.S.).

(ii) any other post under the Central Government or a State Government, the minimum and the maximum of the scale of pay of which were not less than rupees 160 and rupees 450 respectively in the case of a post held prior to 1st July, 1959 and rupees 210 and rupees 530 respectively in the case of a post held on or after 1st July, 1959.'

M. K. VASUDEVAN, Under Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 27th July 1970

CORRIGENDUM

No. 15/1/70-AIS(I).—In the Ministry of Home Affairs Notification No. 15/1/70-AIS (I), dated the 4th April, 1970 published in Part I Section 1 of the Gazette of India dated the 4th April, 1970, the following changes may be effected :—

Reference	Correction
<i>Rules</i>	
Page 330, col. 1, para 1, line 16.	Add the sign '(' before the word 'Reservation'.
Page 330, col. 1, para 1, items (viii) and (ix).	Services may be interchanged.
Page 331, col. 1, Note 3 below para 4, line 5.	For the word 'resuest' read the word 'request'.
Page 331, col. 2, para 6 (i), line 4.	For the word 'Rulet' read the word 'Rule'.
Page 334, col. 2, para 1, below the word Irish Universities.	For the words 'National University of Dublin' read the words 'The National University of Ireland'.

Appendix III

Page 336, col. 2., Note 2 below para 2(e), line 1.	For the word 'increment' read the word 'increments'.
Page 337, col. 1., para 3, line 3.	For the word 'successful' read the word 'Successful'.
Page 338, col. 2, Note 2 below para (1) of item 'Indian Customs and Central Excise Service'.	Add word 'which' between the words 'rules and 'will'.
Page 339, col. 1, item 'Indian Defence Accounts Service', line 2.	For the figure '1,000' read the figure '1,100'.

Reference	Correction
Page 342 col. 2, para '13. Indian Railway Traffic Service, Note 2 below item (m), line 7.	For the word 'even' read the word 'event'.
Page 342, col. 2, para '13. Indian Railway Traffic Service' Note 4 below item (m),	For the word 'old' read the word 'odd'.
Page 342, col. 2, para '13. Indian Railway Traffic Service' Note 4 below item (m), sub-col. 2, sub-item (3).	Delete words 'to harm' between the words 'School' and 'Guard's'.
Page 345, col. 2, para '19. The Railway Board Secretariat Service, Class II item (j) sub-item (b), line 2.	For the word 'funds' read word 'fund'.
Page 347, para '25. Goa, Daman and Diu Civil Services Class II,' item (e) sub-para 4, lines 4 and 5.	(i) Read after the words 'provision of' the words sub-rule (i) of rule 22-B of the'. (ii) After the words 'Fundamental Regulations' delete the figure '22-B (1)'.
Page 347, para 26. Pondicherry Civil Service, Class II' item (e) sub-para 3, lines 4 and 5.	(i) After the words 'provision of' add the words 'sub-rule (1) of rule 22-B of the'. (ii) After the words 'Fundamental Regulations' delete the figure '22-B(1)'.
Appendix IV	
Page 348, para 4 (d) (i), lines 1 and 2.	(i) After the words 'of the' add the word 'Technical'. (ii) For 'under' read 'above' and delete the word 'the'. (iii) Delete the words 'Category Technical' and 'also for'.
Page 348, col. 2, para 5 (g), sub-para 3, line 1.	After the words 'For the' add the words 'Indian Railway Traffic Service and for other'.
Page 348, col. 2, para 5(h) (iii), line 5.	Delete the word 'further' between the words 'provided' and 'that'.
Page 349, col. 1, para 7. Heading 'Method of taking Blood Pressure' sub-para 2, line 16.	For the word 'a' before the words 'Pressure falls' substitute the word 'the'.
Page 350, col. 1, Heading 'Medical Board's Report' sub-para 6, line 5.	After the words 'or otherwise' for the word 'of' read the word 'for'.
Page 350, col. 2, Heading 'Medical Board's Report item (b)—'Report of Medical Board on.....' Note below sub-item (3), sub-col. 1, line 5.	For the word 'Manifest' substitute the word '(Manifest)'.

B. NARASIMHAN, Under Secy.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 8th September 1970

No. 1-11/69-MEI.—Reference the erstwhile Ministry of Steel, Mines and Heavy Engineering Resolution No. 1-2/63-MEI, dated the 25th March, 1964 constituting a Panel for the Ball Bearing Industry and subsequent Notification No. 1-2/63-MEI, dated the 14th May, 1965.

2. It has been decided that Shri P. H. Ghyara, Manager (Ancillaries Development) will represent M/s. Tata Engineering and Locomotive Company Limited, Bombay in place of Shri J. E. Talulicar.

T. V. L. NARASIAH, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT

(Department of Family Planning)

RESOLUTION

New Delhi, the 9th July 1970

No. 8-10/69-NMO/ME(FP).—The Government of India are pleased to constitute a 'Nirodh Advisory Committee.' The composition of the Committee will be as under :—

Chairman

1. Minister of State in the Ministry of Health and Family planning & Works, Housing & Urban Development (In-charge Family Planning).

Members

2. Secretary, Ministry of Health & Family Planning and Works, Housing & Urban Development or his nominee.
3. Dr. D. P. Karmarkar, Institute of Economic Research, Vidyagiri, Dharwar.
4. Shri Rasik Lal Parekh, Shankarbhai's Bungalow Maharashtra Society, Ahmedabad-6.
5. Commissioner, Family Planning, Department of Family Planning.
6. Dr. R. Subramaniam, Chief (Health), Planning Commission.
7. Shri T. S. Nagarajan, Director, Brooke Bond India Ltd., 9 Shakespeare Sarani, Calcutta-16.
8. Shri A. N. Haksar, Chairman, India Tobacco Co. Ltd., Virginia House, 37 Chowringhee, Calcutta-16.
9. A representative of M/s. Hindustan Lever Ltd., Bombay.
10. A representative of M/s. Lipton (India) Ltd., Calcutta.
11. A representative of M/s. Tata Oil Mills Co. Ltd., Bombay.
12. A representative of M/s. Union Carbide (India) Ltd., Calcutta.
13. A representative of Advertising Agencies Association of India Ltd., Bombay.
14. Shri Kisan Mehta, General Manager, The Coca Cola Export Corporation, 14-A, Nizamuddin West, New Delhi-13.

Member-convenor

15. Chairman, Hindustan Latex Ltd., Nirman Bhavan, New Delhi.

Member-Joint convenor

16. Marketing Executive, Department of Family Planning.

2. The terms of reference of the committee will be to consider ways and means of organising an effective and co-ordinated programme for the publicity production and sales promotion of Nirodh (condoms) and to suggest the guidelines in this regard.

3. The Committee shall have the power to co-opt/invite other experts to attend its meetings.

4. Non-official members of the committee shall be entitled to the grant of travelling and daily allowances for attending the meetings of the Committee at the rates admissible to an officer of the highest grade in class I of the Central Services. Members of the Committee who are Government servants will draw travelling and daily allowances as admissible to them from the same source from which they get their pay.

5. The expenditure involved is debitable to Major Head 30. Public Health. B. Public Health B. 5. Miscellaneous B.5(4) Expenditure on Family Planning. B. 5(4)(1) services and supplies B. 5(4)(1)(4) Expenditure on Nirodh Scheme

in Grant No. 38, Medical and Public Health for the year 1970-71.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

R. N. MADHOK, Jt. Secy.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION

(Department of Agriculture)

New Delhi-1, the 19th September 1970

RESOLUTION

THE CENTRAL LAND REFORMS COMMITTEE

No. F. 11-16/70-LRU.—The programme of land reforms has assumed national importance both as in instrumental of social justice and as an important factor for agricultural development in the country. The broad outline of the land policy as followed in the States was enunciated in the First Five Year Plan, which was elaborated in the Second and reiterated in the Third and Fourth Five Year Plans.

2. A review of land reforms reveals that though considerable progress has been achieved in the implementation of land reforms, yet there are many gaps in objectives and legislation and between the laws and their implementation.

3. In November 1969 the various problems of land reforms were considered at length at the Chief Ministers' Conference convened by the Minister of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation. The Conference recommended a minimum programme for speedy implementation of land reform measures. Since the implementation of the programmes are to be handled by the State Governments, the consensus at the Conference was that there should be a Central Body for matching the progress and providing guidance to the State Governments. The need for a Central Committee was also supported by the Planning Commission. In pursuance of these recommendations a Central Land Reforms Committee has been set up composed of the following :—

- | | |
|--|----------|
| (1) Minister of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation | Chairman |
| (2) Minister of Law and Social Welfare | Member |
| (3) Deputy Chairman, Planning Commission | Member |
| (4) Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture | Member |
| (5) Minister of State (Home Affairs) in the Ministry of Home Affairs | Member |
| (6) Member (Agriculture), Planning Commission | Member |

The Prime Minister would also be kept in touch with the activities of the Committee.

4. In consultation with the State Governments, the Central Committee will co-opt one or more members in each State to function as members of the Committee in relation to the programme of work in respect of that State.

5. Secretary (Agriculture) will be the Convenor of the Committee and Joint Secretary incharge of Land Reforms will be the Joint Convenor.

6. The functions of the Central Committee will be as follows :—

- to maintain continuous study of problems relating to the ownership, management, cultivation and distribution of land;
- to assist States in determining and carrying out programme of land reforms;
- to evaluate and report from time to time upon the operation, progress and effects of measures of land reform including enforcement of limits on personal cultivation and ownership, reduction of rent, security of tenure, consolidation of holdings and prevention of their fragmentation, etc.

(iv) to advise on schemes of resettlement on land for the landless agricultural workers, conferment of ownership of homesteads or house sites to the landless agricultural labourers, including members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, and other related problems.

(v) to recommend such measures and adjustments in land policy as may be necessary with a view to the fulfilment of the Directives of State Policy prescribed in the Constitution and the programme and objectives of the Five Year Plans.

(vi) to advise and assist the States in formulating proposals enacting suitable legislation and expediting implementation;

(vii) to entrust special problems for study to individual experts and long-term problems to Land Reforms Centre which is in the process of being set up.

7. The Headquarters of the Central Committee will be at New Delhi.

8. ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

T. P. SINGH, Secy.

MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

RESOLUTION

New Delhi, the 27th August 1970

No. EL.I.32(84)/68.—The following amendments may be carried out in para 3 of this Ministry's Resolution of even number dated the 27th May, 1969, constituting an Expert Committee for going into the question of reduction of construction costs of power stations, reduction of transmission losses etc.

For (v) Shri Ipe Mathai, Member (Commercial), Central Water and Power Commission, New Delhi.—
Member

Read (v) Shri P. P. Gangadharan, Member (Commercial), Central Water and Power Commission, New Delhi.—
Member

For (xi) Shri B. V. Deshmukh, Member (Technical), Maharashtra State Electricity Board, Bombay.—
Member

Read (xi) Shri B. V. Deshmukh, Chairman, Bhakra Management Board, Chandigarh.—
Member

ORDER

ORDERED that the above Resolution may be communicated to the Chairman and Members of the Power Economy Committee, all State Governments and State Electricity Boards for giving wide publicity.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India.

RESOLUTION

The 9th September 1970

No. DW.II-30(208)/70.—The Alaknanda river which rose to an abnormally high stage above its natural level within a very short period, burst its banks on the 20th July 1970 resulting in a high flood carrying heavy silt charge on the following day in the Ganga river at Hardwar, where the headworks of the Upper Ganga Canal are located. The manner of operation of the canal on that day and the few days thereafter led to heavy silting up of the canal in its upper reach to a length of 12 K.M. till it had to be finally closed down. The Government of Uttar Pradesh had to organise immediately an emergent massive silt clearance operation at a heavy expense to ensure rabi irrigation to the area under the command of the canal. In consultation with the Government of Uttar Pradesh, the Government of India have decided to set-up a Committee to enquire, examine and report on the following :—

- The causes that led to the silting of the canal;
- The current rules and regulations for the operation of the canal and their adequacy, and whether they were followed intelligently;

3. Any measures that should have been anticipated and taken to control the situation more effectively, and to make suitable recommendations, both structural and non-structural, to avoid such mishaps in future.

The Committee will consist of the following :—

Chairman

1. Shri N. G. K. Murti, Chairman and Managing Director, Water & Power Development Consultancy Services (India) Ltd., New Delhi.

Members

2. Shri S. K. Jain, Chairman, C.W.&P.C.
3. Shri J. P. Naegamvala, Member, C.W.&P.C.
4. Prof. R. S. Chaturvedi, Harcourt Butler Technical Institute, Kanpur.

5. Shri Jatindra Singh, Retired Chief Engineer (Irrigation), Punjab and Consultant, Ministry of Irrigation and Power, Government of India, New Delhi.

Member Secretary

6. Dr. S. P. Garg, Director, U.P. Irrigation Research Institute, Roorkee.

The Committee will commence work immediately and submit its report within two months to the Government of India in the Ministry of Irrigation and Power.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India Part I, Section 1.

ORDERED also that a copy of the Resolution be communicated to all Ministries/Departments of the Government of India and all State Governments/Administration of Union Territories.

V. V. CHARI, Secy.